न्याय के साथ विकास" को इंगित करती है, अर्थात ऐसा विकास जिसमें जनसंख्या के मध्य लाभों को न्यायसंगत रूप से साझा किया जाता है।

भारत ने समावेशी विकास के कई संकेतकों जैसे कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, मानव विकास सूचकांक, सामाजिक प्रगति सूचकांक जैसे सूचकांकों में सुधार आदि की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रगति की है, हालांकि समावेशी विकास की प्रक्रिया को पूरी तरह से चरितार्थ नहीं किया जा सका है। निम्नलिखित कारणों से भारत में समग्र विकास के लिए समावेशी विकास महत्वपूर्ण है:

- **गरीबी उन्मूलन और आय की असमानता को कम करना:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की लगभग 22% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है। इसके अतिरिक्त, ऑक्सफैम रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की सबसे समृद्ध 1% जनसंख्या के पास देश के निचले 70% जनसंख्या की तुलना में चार गुना से अधिक धन है। ऐसी स्थिति में, संसाधनों के समान वितरण और संधारणीय आर्थिक विकास के माध्यम से समावेशी विकास, लाखों लोगों की निर्धनता को दूर करने और समृद्ध एवं निर्धन के मध्य की खाई को पाटने में सहायता करेगा।
- **बेरोजगारी पर अंकुश:** वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में बेरोजगारी की दर 6 प्रतिशत से अधिक थी, जो 45 वर्ष में सर्वाधिक है। समावेशी विकास, भौतिक अवसंरचना के लक्षित विकास को सुनिश्चित कर सकता है जो भारत में अकुशल / अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए वृहत पैमाने पर रोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण है।
- **स्वास्थ्य सेवा, जल और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार करना:** समावेशी विकास के कारण सस्ती स्वास्थ्य सेवा, दवा की कीमतों पर नियंत्रण, पेयजल की निःशुल्क उपलब्धता और स्वच्छता सुविधाओं का व्यापक विस्तार हो सकता है। इससे उच्च शिशु और मातृ मृत्यु दर, आर्थिक क्षमता से अधिक का स्वास्थ्य व्यय आदि जैसे मुद्दों से निपटने में सहायता मिलेगी।

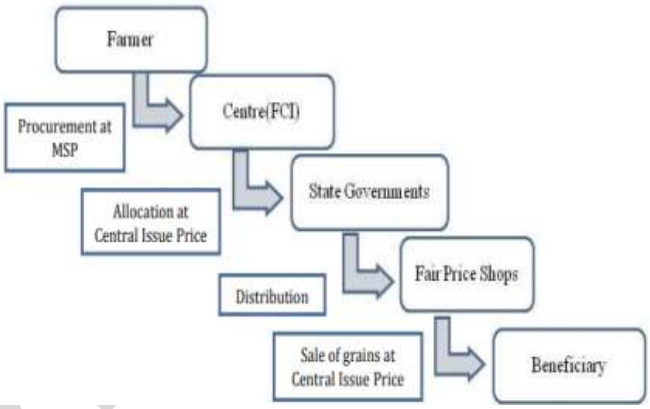

- **शिक्षा क्षेत्रक को संवर्धित करना:** वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 26% भारतीय निरक्षर थे जो विश्व औसत, जो कि लगभग 14% है, से बहुत नीचे है। इसलिए, समावेशी विकास निरक्षरता उन्मूलन और प्राथमिक और तकनीकी शिक्षा का बड़े पैमाने पर विस्तार द्वारा मौजूदा विकास प्रक्रिया में बहिष्कृत एजेंटों के लिए श्रम उत्पादकता और लाभकारी रोजगार के अवसर को बढ़ा सकता है। इससे भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश क्षमता का इष्टतम उपयोग भी संभव होगा।
- **समावेशी कृषि:** चूंकि भारत में कृषि सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्रक है, इसलिए इसके विकास का लाखों लोगों के कल्याण से सीधा सह-संबंध है। किसानों के लिए कम आय, संस्थागत ऋण तक पहुंच की कमी आदि जैसी चुनौतियों से निपटने में समावेशी कृषि सहायता करेगी।
- **पर्यावरणीय संधारणीयता:** संधारणीय पर्यावरण विकास, समावेशी विकास के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। इस प्रकार, समावेशी विकास भूमि के क्षरण, प्रदूषण आदि जैसी समस्याओं पर नियंत्रण करके पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देगा।

सरकार ने इस संदर्भ में कई पहलें आरम्भ की हैं जैसे कि **जन धन योजना, मनरेगा (MGNREGA), सर्वशिक्षा अभियान, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री-किसान योजना** इत्यादि। हालांकि, बहुआयामी समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए और अधिक उपायों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, मुख्यधारा से अभी तक अलग-थलग रहे समूहों, जैसे दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, बुजुर्ग आदि को आगे बढ़ती हुई विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने की आवश्यकता है।

8. Highlight the potential, significance and challenges facing the food processing sector in India.

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की क्षमता, महत्व एवं इस क्षेत्रक द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।